Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

ग्रामीण भारत में सामाजिक परिवर्तन

प्रो. आरती बारोठिया*

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) भेरूलाल पाटीदार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महू (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – भारत की कुल 1 अरब 25 करोड़ आबादी है, जो विश्व की 17.5% के बराबर है। उसमें से ग्रामीण क्षेत्र में 65% जनसंख्या निवास करती है। वर्तमान में कुल 6.38 लाख गांव है। भारत गांव का देश है, अर्थात गांव की तरक्की के बिना भारत की उन्नति नहीं हो सकती। विकास के कई पहलू है ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग धारणा प्रस्तुत करती है।ये मनुष्य की सभी आकांक्षा और इच्छाओं से जुड़ी होती है जो उनके सर्वांगीण विकास के लिए अति आवश्यक है। विकास से प्रगति दिखती हैं जो लोगों के जीवन पर प्रभाव डालती है। बीसवीं शताब्दी में ग्रामीण सामाजिक संरचना में परिवर्तन से भारत की जीडीपी में वृद्धि हुई तथा यह विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, लेकिन इन सब का फायदा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को कितना मिल रहा है, यह वास्तव में देखने की बात है। 1990 दशक के बाद से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव दिखाई देने लगा, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास सामाजिक परिवर्तन का साधन है, ग्रामीण विकास से तात्पर्य है शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, आवास, मूलभूत सुविधाओं को विकसित करना, गरीबी को दूर करना, शासन की योजनाओं में ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित कर जागरूकता और चेतना का संचार करना। इस प्रकार की व्यवस्था से ही गांव के लोगों का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास होना संभव है। सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गांव में बुनियादी सुविधाओं, आधारभूत संरचनाओं के निर्माण द्वारा ग्रामीण भारत के स्वरूप को बदलने के लिए विशेष अवसर उपलब्ध करा रही है। गरीबों, महिलाओं, कमजोर और निर्बल वर्गों के लिए कई कल्याणकारी और विकास की योजनाएं लाई गई है। इन सब का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों के बीच व्याप्त विषमताओं को कम करना, संतुलित सामाजिक विकास प्राप्त करना है। इनमे तत्कालीन कदम मनरेगा, भारत निर्माण एवं खाद्य सुरक्षा हो सकते है। नई सरकार द्वारा अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना ने लोगों को बैंक में खाता खोलकर बचत करनी की परंपरा की नींव डाली है। बचत किसी भी परिवार और समाज की आर्थिक संतुलन को बनाए रखने के लिए भूमिका निभाती है। इससे देश की विकास की योजनाओं के कार्यान्वयन में बड़ा योगदान होता है। स्वच्छ भारत अभियान ने भी लोगों को अपने कर्तव्यों और दायित्वों का ज्ञान कराया, इस प्रकार बदलती हुई राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में बहुआयामी सामाजिक परिवर्तन हेतु ग्रामीण समाज का पुनर्निर्माण करने के बराबर है । योजना आयोग द्वारा जारी वर्ष 2012 को भारतीय निर्धनता अनुपात 29.8 जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 33.8% था।

उद्देश्य:

1. विकासशील भारतीय अर्थव्यवस्था में गांव की भूमिका।
2. ग्रामीण जीवन शैली पर विभिन्न योजनाओं का योगदान।
3. भारत के संतुलित विकास का अध्ययन ।
4. ग्रामीणों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को जानना।

गांव में स्त्री, पुरुष, लड़के लड़कियों सभी में साक्षरता बढ़ रही है। बुनियादी शिक्षा तथा समाज शिक्षा बढ़ती जा रही है। अनेक राज्य प्रत्येक बालक बालिका के लिए अनिवार्य शिक्षा का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। गांव में बहुत से युवक उच्च शिक्षा प्राप्त करने शहरों की ओर जाने लगे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण संस्थाएं कृषि कॉलेज, डिग्री कॉलेजों की स्थापना की गई है। लोगों की जीवन शैली बदल रही है, इससे नई नई चीजों का बाजार फल फूल रहा है। शिक्षित वर्ग का नौकरी की ओर अधिक झुकाव हुआ है, नए औजार, नए बीज, नई खेती के तरीकों से उत्पादन बढ़ गया है। सहकारी समितियों की स्थापना, अनाज बैंक और सरकारी बैंकों के खुलने से ऋणग्रसिता कम हो गई है। सरकारी सहायता से लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास हुआ है। किसानों और छोटे व्यापारियों की दशा में सुधार आया है। पंचायतों की स्थापना से गांव में राजनीतिक क्षेत्र में जागरूकता बढ़ गई है। अखबार, रेडियो, टीवी के माध्यम से वे अपने अधिकारों के प्रति जागृत हुए हैं। राष्ट्रीय चेतना जागृत होने पर भी, सामुदायिक भावना कम हुई है। भारत के ग्रामीण समुदाय में तीव्रता से परिवर्तन होते जा रहे हैं। नगरों के पास के गांव में रहन–सहन, खान–पान, जीवन पद्धति में परिवर्तन देखने को मिलता है।

सामाजिक परिवर्तन के मुख्य तत्वों की पहचान निम्न है –

1. शिक्षा का विकास
2. राजनीति में युवाओं की भूमिका
3. सामाजिक मूल्य का असर आधारभूत सुविधाएं
4. आम लोगों की प्रवृत्ति में परिवर्तन
5. प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग
6. नवीन तकनीकी और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल
7. समाजवाद की ओर बढ़ते हुए कदम आदि।

यह मानव के कल्याण की ओर संकेत कर रहे हैं जो आर्थिक विकास के लिए सामाजिक प्रभाव की तस्वीर प्रस्तुत करता है। ग्रामीण क्षेत्र की

अर्थव्यवस्था का प्रभाव राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है ग्रामीण आबादी की बड़ी संख्या कृषि पर आधारित है क्योंकि वहां के किसान अशिक्षित है और कुछ खेती की बारीकियों से नासमझ है, इसके निदान के लिए सरकार ने कृषि मित्र, किसान कॉल सेंटर, किसान क्रेडिट कार्ड जैसे कदम उठाए हैं। ग्रामीण जनसंख्या का 30% लोग खेती नहीं करना चाहते। ग्रामीण विकास और सामाजिक परिवर्तन में पंचायती राज संस्थान सराहनीय योगदान दिया है। इसे एक क्रांतिकारी बदलाव कह सकते हैं, महिलाओं को मिले आरक्षण से पुरुषवादी प्रवृत्ति पर अंकुश लगा है। महिलाएं राजनीतिक भागीदारी के साथ आर्थिक रूप से भी सशक्त हो रही हैं, वे समाज के सशक्त विकास से बच्चों और महिलाओं के विकास को प्राथमिकता दे रही है ।पंचायती राज संस्थाओं में छोटे-छोटे पदों पर चुनी प्रतिनिधियों की संख्या गांव में लगातार बढ़ती जा रही है। विभिन्न तरह के विकास के बदलाव से ग्रामीण परिवेश में परिवर्तन देखने को मिलता है इस आर्थिक युग में ग्रामवासी के पास फालतू बातचीत, कार्यों के लिए समय नहीं है। यह बढ़ती महंगाई का परिणाम हो सकता है, जिसने ग्रामीणों लोगों मै शहरों की प्रवृत्ति ला दिया है सामाजिक मूल्य का हास देखने को मिल रहा है जिससे परिवार का स्वरूप बदलने लगा है। आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन का कारण बन गया है।

गांव से शहरों की ओर पलायन की प्रवृत्ति बढ़ रही है। गांव मे एक आदमी का शहरीकरण होने से एक नई संस्कृति का जन्म होता है। गांव में शिक्षा के विकास से जागृत आने से अधिकांश ग्रामवासी पुरानी रूढ़िवादिता के चक्कर में फस नहीं जाते। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, जिसके द्वारा सामाजिक परिवर्तन फल फूल रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत सबको शिक्षा दी जा रही है, लेकिन शिक्षकों की नियुक्ति और मध्यान्ह योजना ने शिक्षा का स्तर गिरा दिया है। गांव में लड़कियों को शिक्षित करने की योजना सामाजिक परिवर्तन को लाने का मुख्य कारण बनी हुई। महिला साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, ग्रामीण विकास में स्वयंसेवी संगठनों, रेड क्रॉस, सामाजिक न्याय दिलाने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा दे रही हैं। गांव में कानून व्यवस्था के कारण सरपंचों को कई प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं। ग्रामीणों की प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि दिखाई दे रही है।

औद्योगिकरण, शहरीकरण, परिवहन के साधनों में वृद्धि, अंग्रेजी शिक्षा की लोकप्रियता सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता, छुआछूत को दूर करने वाले कानून ने जातिवाद के प्रभाव को प्रभावों को कम कर दिया है। अब ग्रामीण कमजोर व अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए। जिससे समाज में तेजी से परिवर्तन दिखाई देने लगा है। सूचना के अधिकार 2005 में ग्रामीण प्रशासन में पारदर्शिता ,जवाबदेही जिससे ग्रामीणों को विकास से जुड़े समाधान करने में बाधाओं को दूर करने में मदद मिलती है।

ग्रामीण विकास के साथ अगर तेजी से सामाजिक परिवर्तन की संभावना को प्रोत्साहन देना है तो निम्न बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है।

1. शिक्षा के व्यवसायीकरण को कम करते हुए इसमें अधिगम एवम समानता के साथ गुणवत्ता भी लाई जाए।
2. शोध और विकास को गांव से संबद्धता प्रदान की जाए।
3. सरकारी नीतियों का सामाजिक परिवर्तन का लक्ष्य एवम सर्वोच्चता रखना।
4. सभी के प्रयास और एकजुटता

ग्रामीण पर सामाजिक परिवर्तन तेजी से ना होने के कारण है कि ग्रामीण जनता को संख्या समझा जाता है, लेकिन अगर उसको मानव संसाधन में परिणित कर दिया जाए तो वह एक स्थाई संपत्ति बन सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन का दायरा परंपरागत विकास से काफी व्यापक है इसमें विकास के विभिन्न आयामों के साथ-साथ विकास, भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी, गुणवत्तापुर्ण जीवन के लिए जरूरतों की पूर्ति जैसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल है। कृषि की स्थिति स्वतंत्रता के समय देश अनाज की कमी से जूझ रहा था आजादी के बाद भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भूमि सुधार, हरित क्रांति, प्रौद्योगिकी, नवाचार, मशीनीकरण जैसे अनेक कदम उठाए गए। वर्तमान में भारत का खाद्यान्न उत्पादन में दूसरा स्थान आज भी 50.8% से अधिक परिवार अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। वर्ष 2020-21 के अनुसार कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 20% योगदान है।

निष्कर्ष – ग्रामीण भारत के विकास के लिए आजादी के बाद से कई प्रयास किए गए। जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक ढांचे में बदलाव देखने को मिला है। आज भी देश के कई गांवों को सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, तकनीकी उद्योग समृद्धि का समुचित लाभ नहीं मिल रहा है। अत: आज की सरकार को अपनी योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता देने के साथ, उन्हें धारा पर लागू करना चाहिए। प्रत्येक ग्राम गरीबी से मुक्त, उन्नत आर्थिक, सामाजिक रूप से सक्षम बनेगा, तभी देश का विकास होगा। निम्न योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है।

1. दीनदयाल उपाध्याय
2. ग्रामीण कौशल योजना
3. स्वच्छ भारत मिशन
4. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
5. स्वरोजगार के लिए ग्रामीण
6. युवाओं को प्रशिक्षण
7. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
8. सर्व शिक्षा अभियान
9. कुटीर ज्योति कार्यक्रम
10. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

भारतीय समाज प्राथमिक रूप से ग्रामीण समाज ही है, जहां नगरीकरण बढ़ रहा है, भारत के बहुसंख्यक लोग गांव में ही रहते हैं और उनका जीवन कृषि और संबंधित व्यवसाय से चलता है बहुत से भारतीयों के लिए भूमि उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन है। ना केवल जीविका बल्कि कृषि जीने का एक तरीका भी है। कृषि और संस्कृति के बीच घनिष्ठ संबंध है हमारे देश में कृषि की प्रकृति भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग है। ग्रामीण सिर्फ कृषि ही नहीं बहुत से ऐसे क्रियाकलाप, जो कृषि और ग्रामीण जीवन की मदद के लिए हैं, वे ग्रामीण भारत में जीविका के साधन थे। बहुत से कारीगर, दस्तकार कुम्हार, सुनार आदि ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। विकास के साथ-साथ मशीन से बने सामानों के आगमन ने हाथ से बनी वस्तुओं का रूप ले लिया। ग्रामीण भारत में व्यवसाय विभिन्नता यहां की जाति व्यवस्था में प्रतिबंधित होती है। कुछ परंपरागत व्यवसाय आज टूट रहे, लेकिन ग्रामीण शहरी के परस्पर संबंध से कई व्यवसाय गांव में आ रहे हैं। बहुत से लोग गांव में रहते हैं नौकरी करने या उनकी जीविका ग्रामीण कृषि क्रियाकलापों में आधारित है।

अधिकांश गांव की समाज परंपरागत तरीकों से संचालित होती है, इसलिए संस्थाएं, जाति, धर्म, सांस्कृतिक प्रथाओं के दूसरे स्वरूप यहां अधिक प्रभावशाली है। ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति संरचना के संदर्भ में होने वाले परिवर्तन और भी धीमा होता है। सरकार द्वारा मनरेगा,ग्रामीण विकास योजना का प्रभाव गांव के जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य दृष्टिगोचर होने लगा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. भारतीय अर्थव्यवस्था – दत्त एवं सुंदर।
2. कुरुक्षेत्र जनवरी 2015
3. दृष्टि अकैडमी।
4. आई ए एस।

****